राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 24 दिसंबर 2025

वर्ष 14,अंक 251, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

युवक पर धारदार हथियार से किया ताबड़तोड़ हमला सिर-गले पर गहरे जख्म, हालत गंभीर लखनऊ रेफर..03

बलिया नगर के वार्ड नंबर 5 में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम हेतु छिड़काव की मांग..04

अरावली विरासत जन अभियान की मांग- ऊंचाई की शर्त के बिना सभी अरावली पहाड़ियों को संरक्षण दें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अरावली की पहाड़ियों के लिए दी गई नई परिभाषा को स्वीकारे जाने के बाद से 4 राज्यों के बीच लगभग 700 किलोमीटर तक फैली अरावली के अस्तित्व को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. नई परिभाषा के हिसाब से ज़मीन से कम से कम 100 मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी. इसे लेकर राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच सोमवार (22 दिसंबर) को अरावली विरासत जन अभियान ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई अरावली पर्वतमाला की एक समान (यूनिफ़ॉर्म) परिभाषा को लेकर सरकार की हालिया सफ़ाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. बयान में कहा गया हैः हमारी पहली चिंता यह है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा दिए गए वीडियो बयान और 21 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई जानकारी के बीच स्पष्ट विरोधाभास है. भाजपा की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'वर्तमान में अरावली क्षेत्र 37 ज़िलों में फैला हुआ है. इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो 37 ज़िलों में विस्तृत है. इनमें से अकेले राजस्थान के 20 ज़िलों में यह पर्वतमाला फैली हुई है. कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.19 प्रतिशत, यानी 277.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही वैध खनन पट्टों के अंतर्गत है।'

वहीं, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने वीडियो

बयान में कहा, 'अरावली का कुल क्षेत्रफल 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है. कुल 39 अरावली ज़िले हैं. इनमें से केवल 217 वर्ग किलोमीटर, यानी 2 प्रतिशत क्षेत्र में खनन हो सकता है. पहाड़ियों को नीचे से ऊपर तक 100 मीटर ऊंचाई तक संरक्षित किया जाएगा.' अरावली विरासत जन अभियान ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से पारदर्शिता की मांग करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से निम्नलिखित स्पष्टीकरण और जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की हैः-

1) दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन चार अरावली राज्यों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार अरावली ज़िलों की वास्तविक संख्या क्या है और उनके नाम क्या हैं?

2) फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) की परिभाषा के अनुसार कुल कितनी पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी? 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई नई 100 मीटर की परिभाषा के अनुसार कितनी पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी? दोनों परिभाषाओं के तहत अरावली का कुल क्षेत्रफल कितना होगा?

चूंकि एफएसआई के पास पहले से ही राजस्थान के 15 ज़िलों का डेटा उपलब्ध है, इसलिए इन 15 ज़िलों के लिए नई 100 मीटर की परिभाषा और एफएसआई परिभाषा, दोनों के तहत पहाड़ियों की संख्या और अरावली क्षेत्रफल से संबंधित आंकड़े तत्काल सार्वजनिक किए जाएं।

3) क्या केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि अरावली का हिस्सा होने की स्थिति में, पहाड़ियों की ऊंचाई चाहे जो भी हो, सभी पहाड़ियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा?

अरावली विरासत जन अभियान की दूसरी चिंता यह है कि सरकारी 'प्रेस विज्ञप्ति की शुरुआत में अरावली को केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों से भरा हुआ क्षेत्र बताया गया है. अरावली के परिचय में इसकी समृद्ध जैव विविधता, जंगलों, नदियों, जलधाराओं और उन समुदायों का कोई उल्लेख नहीं है, जो अरावली पर निर्भर हैं. यह हैरान करने वाला है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला को केवल किलों, मंदिरों, मीनारों और सांस्कृतिक स्थलों के संदर्भ में ही वर्णित किया गया है.' संगठन का तीसरा बिंदु यह है कि 'केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यह कह रहे हैं कि 20 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अरावली का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रभावित नहीं होगा. यदि ऐसा है, तो अरावली विरासत जन अभियान मांग करता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के प्रत्येक अरावली ज़िले के हर ब्लॉक में, ग्रामीण और शहरी आबादी के साथ तत्काल परामर्श आयोजित करे और लोगों को यह स्पष्ट करे कि अरावली की नई परिभाषा अरावली के संरक्षण और सुरक्षा को मज़बूत करेगी।'

अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया

इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार (22 दिसंबर) को केंद्र सरकार पर पर्यावरणीय सुरक्षा को कमजोर करने और संवेदनशील अरावली पर्वतमाला में खनन का रास्ता खोलने के लिए एक 'सुनियोजित साज़िश' रचने का आरोप लगाया है. गहलोत ने कहा कि अरावली की परिभाषा को '100 मीटर' के मानक से दोबारा तय करने के सरकार के कदम को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता. उन्होंने कहा, 'यह संस्थाओं पर कब्ज़ा करने और अरावली को खनन माफिया के हवाले करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है.' उन्होंने केंद्र के कुछ बड़े कदमों के बारे में कहा कि वे उनके 'असल एजेंडा' को उजागर करते हैं. और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के इस दावे को कि अरावली का केवल 0.19 प्रतिशत हिस्सा ही खनन के लिए खुलेगा, 'भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत' बताया. गहलोत के अनुसार पहला कदम 5 सितंबर 2023 की वह अधिसूचना थी, जिसके तहत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया और उसकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई. उन्होंने कहा, '2002 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वनों की सुरक्षा के लिए गठित सीईसी को अब सरकार की कठपुतली बना दिया गया है. पहले इसके सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट की मंजूरी से होती थी, आज केंद्र सरकार नियुक्तियों को नियंत्रित कर रही है, जिससे सीईसी महज़ एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है।'

मनरेगा के बाद नोट से हटेंगे गांधी, हो चुकी है हाई-लेवल मीटिंग, केरल के सांसद जॉन ब्रिटास का दावा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बीते दिनों संसद के शीत सत्र में केंद्र सरकार ने वीबी-जी राम जी बिल पास करवा लिया. इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. यह बिल देश में रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा की जगह लेगा. सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह से नया बिल है. वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए यह कानून बनाया है. इसको लेकर जारी विवाद के बीच केरल से माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा के बाद अब नोट से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की योजना बना रही है. इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है. माकपा के राज्यसभा सांसद ब्रिटास ने दावा किया है कि भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात को खारिज करे लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महात्मा गांधी की तस्वीर को भारतीय मुद्रा नोटों से हटाने की योजना बना रही है. ब्रिटास ने सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हाई-लेवल

बैठक पहले ही हो चुकी है, जिससे सरकार की सोच में बदलाव का संकेत मिलता है।

हाई लेवल मीटिंग होने का दावा

ब्रिटास ने कहा कि आधिकारिक इनकारों के बावजूद इस मुद्दे पर पहली दौर की उच्च स्तरीय चर्चा हो चुकी है. यह अब मेरा अनुमान नहीं है. गांधी को हमारी मुद्रा से हटाना राष्ट्र के प्रतीकों को फिर से लिखने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है. केंद्र गांधी की तस्वीर को भारत की संस्कृति को बेहतर प्रतिबिंबित करने वाले किसी अन्य प्रतीक से बदलने पर विचार कर रहा है, जिसमें भारत माता भी एक विकल्प है. हालांकि सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि मुद्रा नोटों के डिजाइन पर निर्णय आरबीआई लेता है, जो केंद्र के साथ परामर्श में होता है. महात्मा गांधी की तस्वीर 1996 में सभी नोटों पर स्थायी रूप से आ गई थी, जब महात्मा गांधी सीरीज के नोट लॉन्च किए गए थे. 2022 में आरबीआई ने स्पष्ट रूप से खबरों को खारिज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि गांधी की तस्वीर को रवींद्रनाथ टैगोर या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अन्य हस्तियों की तस्वीर से बदलने का प्रस्ताव है।

क्या है विवाद

यह मुद्दा फिर से सामने आया है, जब विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश करने के बाद आपत्ति जताई. इस बिल में गांधी का नाम हटा दिया गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREG) में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए. विपक्षी दलों ने सरकार पर राम के नाम का उपयोग कर योजना को राजनीतिक रंग देने और गांधी की विरासत मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि नया कानून मनरेगा के मुकाबले काफी है. मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है।

मनरेगा मजदूरों को सात दिन में होगा भुगतान और मिलेगी 125 कार्यदिवस की गारंटी: योगी सरकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम्य विकास राज्यमंत्री विजय लक्ष्?मी गौतम ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी 252 रुपये निर्धारित है और चूंकि यह निर्धारण भारत सरकार से होता है, इसलिए इसमें राज्य सरकार से वृद्धि अपेक्षित नहीं है। गौतम ने कहा कि मजदूरों का भुगतान 15 दिन के बजाय अब सात दिन में ही कर दिया जाएगा। उन्होंने मनरेगा की जगह लेने वाले विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम को विकास में सहायक और प्रभावी बताते हुए यह दावा भी किया कि अब मजदूरों का कार्य दिवस सौ दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गारंटी कर दी गई है और इसे विकसित भारत से जोड़ा जाएगा।

विपक्ष ने उठाया सवाल तो सरकार ने दिया जवाब

विधानसभा शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी (सपा) सदस्य अनिल प्रधान के प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि मनरेगा के मजदूरों को प्रतिदिन 252 रुपये की दर से मजदूरी प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मनरेगा मजदूरों की दर 252 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 700 रुपये किए जाने और वार्षिक कार्य दिवस 300 दिन करने के प्रधान के सवाल पर गौतम ने कहा कि मजदूरी दर निर्धारण एवं अधिकतम रोजगार दिवस निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही होता है, इसलिए इस विषय पर राज्य सरकार से निर्णय अपेक्षित नहीं है।

दो सौ करोड़ रुपये यूपी में मजदूरों का बकाया है

इसके पहले पूरक प्रश्न के दौरान अनिल प्रधान ने कहा कि मनरेगा योजना एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने इसके नाम में परिवर्तन किया और पहले केंद्र सरकार 100 प्रतिशत भुगतान करती थी लेकिन नये प्रावधान में यह व्यवस्था बदल दी गई। सपा सदस्य ने सदन में दावा किया कि दो सौ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में मजदूरों का बकाया है। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई में उनकी दिनचर्या कैसे चलेगी, यह गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि जब सरकार तकनीक में आगे होने का दावा करती है तो भुगतान में इतना समय क्यों लगता है।

सौ दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने की गारंटी

लक्ष्?मी गौतम ने कहा कि अब मजदूरों का भुगतान 15 दिन की बजाय सात दिन के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर बिना नाम लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2009 से पहले यह नरेगा था और फिर जब चुनाव आया तो याद आया कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाए और इसका नाम मनरेगा हो गया। उन्होंने मनरेगा की जगह लेने वाले विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम को विकास में सहायक और प्रभावी बताते हुए यह भी दावा किया कि अब मजदूरों का कार्य दिवस सौ दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने की गारंटी कर दी गई है और इसे विकसित भारत से जोड़ा जाएगा।

संक्षिप्त ख़बरें

रांची के होटवार जेल में कैदियों के डांस वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांची- झारखंड हाईकोर्ट में रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार जेल) में शराब व जीएसटी घोटाला के आरोपियों का डांस करते वीडियो सामने आने के बाद स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को पूरे मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की घटना शर्मनाक है। अदालत अब इस मामले में छह जनवरी को अगली सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज ने बताया कि जेल में नाच प्रकरण के बाद सोशल मीडिया अकाउंट से माफिया एवं सरगनाओं के द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों की खबर समाचार पत्रों के माध्यम से आने पर झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राज्य की एजेंसी के लिए शर्मनाक चिंताजनक स्थिति है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए छह जनवरी का समय निर्धारित किया गया है।

किसानों की हितरक्षा हेतु समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह : चंद्रभूषण

देवरिया। पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता, स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के डुमरी स्थित सपा जनसंपर्क कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सपा के पूर्व प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवनभर किसानों, मजदूरों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहे। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ के नूरपुर गांव में जन्मे चौधरी चरण सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में डांडी मार्च के दौरान हिण्डन नदी पर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा, जिसके लिए उन्हें छह माह की सजा हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हिजबुल सरगना के बेटों को झटका, टेरर फंडिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटों समेत अन्य लोगों की याचिका खारिज कर दी. इन याचिकाओं में टेरर फंडिंग केस में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई थी. जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की बेंच ने अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे सुनवाई योग्य नहीं हैं. आरोपियों ने 2021 में ट्रायल कोर्ट के उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को चुनौती दी थी. नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) के मुताबिक यह मामला पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा हवाला चैनलों के जरिए जम्मू और कश्मीर में पैसे ट्रांसफर करने से जुड़ा है. यह सब भारत में कुछ लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश के तहत किया गया था, ताकि जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें फंड दिया जा सके।

ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज

हाई कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेताओं मसरत आलम भट, शब्बीर अहमद शाह, नईम अहमद खान, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली और अन्य द्वारा UAPA के तहत टेरर फंडिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया।

पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करने का आरोप

हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन के छोटे बेटे शाहिद यूसुफ समेत अन्य आरोपियों ने टेरर फंडिंग मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी. यूसुफ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी अभियानों के लिए पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करने का आरोप था और 2019 में इस मामले में उसके और अन्य 18 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

शाहिद यूसुफ को 2017 में गिरफ्तार किया गया

सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को अक्टूबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था. वहीं, उसके दूसरे बेटे सैयद अहमद शकील को एनआईए ने 30 अगस्त 2018 को श्रीनगर में उसके घर से 2011 में दर्ज टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. दोनों पर आरोपी है कि उन्होंने विदेशी स्रोतों और आतंकवादी संगठनों से पैसे लिए और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

कार्बी आंगलोंग में बेदखली की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन, भाजपा नेता के घर में आगजनी, पथराव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले में बेदखली की मांग से जुड़े विरोध प्रदर्शन सोमवार (22 दिसंबर) को हिंसक हो उठे. प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य और भाजपा नेता तुलीराम रोंगहांग के डोंगकामुकाम स्थित पुश्तैनी घर में आग लगा दी और पथराव किया. इस बीच, प्रशासन ने जिले में तनाव बढ़ने के बाद सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने पर कम से कम तीन लोग घायल हुए. शाम को अतिरिक्त पुलिस बल, सीआरपीएफ और पुलिस कमांडो मौके पर भेजे गए और जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था भंग होने और जन-जीवन व संपत्ति को खतरा होने की आशंका जताते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए. ज्ञात हो कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग एक आदिवासी बहुल पहाड़ी जिला है, जो संविधान की छठी अनुसूची के तहत कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है. ज़िले में तनाव उन नौ लोगों के आमरण अनशन से जुड़ा है, जो पिछले दो हफ्तों से परिषद क्षेत्र के प्रोफेशनल ग्रेज़िंग रिज़र्व (पीजीआर) और विलेज ग्रेज़िंग रिज़र्व (वीजीआर) (आरक्षित चरागाह भूमि) पर बेदखली की मांग को लेकर फेलांगपी में धरने पर बैठे हैं, जो कार्बी आदिवासी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग है. तनाव तब बढ़ गया जब सोमवार को अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों को फेलांगपी से हटाकर ले जाया गया. क़ानून-व्यवस्था के आईजीपी अखिलेश सिंह ने कहा कि उन्हें 'मेडिकल कारणों से' गुवाहाटी ले जाया गया क्योंकि 15 दिन के अनशन के बाद उनकी हालत बिगड़ सकती थी. पथराव और झड़प के दौरान तीन प्रदर्शनकारी और कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. स्थिति काबू में लाने के लिए पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा. इसके अलावा, भीड़ ने पास के बस्ती क्षेत्र में कई घरों, एक स्कूल बस और अन्य ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया।

हिंसा के बाद रोंगहांग ने मीडिया से कहा कि इसे गिरफ्तारी के रूप में 'ग़लत' समझा गया. उन्होंने कहा, 'हमें उनके अनशन से आपत्ति नहीं है, लेकिन मामला बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. हमने उन्हें दीफू आकर चर्चा करने के लिए कहा था और आज शाम 4 बजे परिषद के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक तय थी... लेकिन कल पुलिस कुछ लोगों को इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ले

गई. लोगों के मन में यह गलतफहमी फैल गई कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है.' इसी भ्रम ने इलाके में अशांति को हवा दी, जो अंततः डोंगकामुकाम में सीईएम रोंगहांग के घर में आगजनी तक पहुंच गई. अधिकारियों के अनुसार, वे इस घर में नहीं रहते और वर्तमान में दीफू में रहते हैं. आईजीपी सिंह ने कहा, 'उन्होंने सीईएम के पुश्तैनी घर में आग लगा दी, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा. स्थिति शाम तक नियंत्रण में आ गई. इसके बाद खेरीनी में फिर तनाव शुरू हो गया, जहां भीड़ ने थाने के पास पथराव किया और बिहारी तथा नेपाली समुदाय के लोगों पर हमले की कोशिश की. अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं और सीआरपीएफ तथा कमांडो क्षेत्र में मौजूद हैं।'

अखबार के अनुसार, फरवरी 2024 में रोंगहांग ने घोषणा की थी कि कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में आरक्षित चरागाह भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे. उन्होंने कहा था कि सिर्फ कार्बी आंगलोंग के डोंगकामुकाम क्षेत्र के हवाइपुर मौज़ा में पीजीआर और वीजीआर भूमि पर 1,983 परिवार अवैध तरीके से बसे हैं और फूलोनी क्षेत्र में 103 परिवार चरागाह भूमि पर कब्जे किए हैं. उस समय विरोध तब भड़का था, जब बिहारी नोनिया समुदाय के एक संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देकर इन बस्तियों को वैध करने की मांग कर दी थी. हालांकि बेदखली नहीं की जा सकी. रोंगहांग ने कहा कि यह मामला गौहाटी हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका के कारण रुका हुआ है. उन्होंने कहा, 'हमने सभी संगठनों के साथ मिलकर पीजीआर-वीजीआर भूमि से बेदखली का फैसला किया था और 15 दिन में हटने का नोटिस भी दिया था. लेकिन उसके बाद वहां बसे लोगों ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दी. जब तक मामला अदालत में है, अगर अभी बेदखली की जाए तो यह अदालत की अवमानना होगी।'

हिंसक विरोध के बाद धारा 163 लागू

कार्बी आंगलोंग की जिला उपायुक्त निरोला फांगचोपी द्वारा जारी निषेधाज्ञा के तहत 22 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक यह धारा लागू रहेगी, ताकि 'असमाजिक तत्वों' द्वारा किसी भी तरह के जातीय या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और जन-जीवन व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके. आदेश के अनुसार, पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों और निजी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है. सार्वजनिक स्थानों पर रैली, पिकेटिंग, मशाल जुलूस या धरना नहीं किया जा सकेगा. हथियार ले जाना, आतिशबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा. भड़काऊ या राष्ट्र-विरोधी भाषण, पोस्टर या दीवार लेखन पर रोक है. बिना अनुमति लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन का उपयोग भी मनाही है. हालांकि, पुलिस, सेना और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे. मेडिकल आपात स्थिति में लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के लिए) तथा सरकारी व निजी कार्यालय सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे।

जिलाधिकारी ने दिवंगत अग्निवीर जवान अश्विनी कुमार को दी श्रद्धांजलि

देवरिया। अग्निवीर योजना के अंतर्गत भारतीय सेना की 15 राजपूत रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे जनपद देवरिया के ग्राम खरवनिया (पिंडी) निवासी वीर जवान अश्विनी कुमार का उपचार के दौरान सेना के चिकित्सालय में दुखद निधन हो गया। उनके असामयिक निधन की सूचना मिलते ही जनपद एवं क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत जवान का पार्थिव शरीर गृह ग्राम पहुंचने पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उनके आवास पर पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा में दिवंगत जवान का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवार को मिलने वाली सभी सहायता समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

प्रेम, समानता और एक ही ईश्वर की रचना लिखने वाले बाला प्रीतम हिन्द के पीर गुरु गोविंद सिंह

गुरु गोविंदसिंह जी की जन्म जयंती पर विशेष

सिखों के दसवें तथा मानवीय रूप में अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। नौ वर्ष की आयु में ये 24 नवंबर 1675 को गुरु बने इस संसार से विदा लेने से पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का अगला गुरु घोषित किया था। खालसा पंथ की स्थापना करके उन्होंने सिख धर्म को मौजूदा स्वरूप प्रदान किया उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्ण करना भी शामिल है।नौवें सिख गुरु गुरुतेग बहादुर और उनकी पत्नी माता गुजरी के यहां पटना में जन्में गोविंद सिंह का प्रारंभिक नाम गोविंद राय था।जन्म के समय उनके पिता आसाम को धार्मिक यात्रा पर थे। जनश्रुति है कि वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले के ठाकसा गांव के एक फकीर पीर भीकन शाह ने उनके जन्म की भविष्य वाणी पहले ही कर दी थी। एक दिन नमाज करते वक्त भीकन शाह ने पूरब की तरफ सिजदा किया जबकि इस्लामिक उपासना पद्धति में पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है।जब गांव वालों ने उनसे उनके इस आश्चर्य भरे व्यवहार के बारे में पूछा तब पीर साहब ने बताया जिसे ईश्वर ने उद्धारक के तौर पर चुना है, पटना में पैदा होगा।जो कि पूरब में पड़ता है।इसके बाद पीर भीकन शाह अपने कुछ शिष्यों के साथ उस बच्चे को देखने पटना गए।उन्होंने मिठाई से भरे दो कटोरे उस बच्चे के आगे रखे एक कटोरा मिठाई हिंदू के यहां से और दूसरे कटोरे की मिठाई मुसलमान के यहां से खरीदी गई थी। जो इस बात का प्रतीक थी कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दो प्रमुख धर्म हैं। बच्चे ने दोनों कटोरों पर अपने हाथ रख दिए जो इस बात का सबूत था कि उसके द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों से बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार अंबाला जिले के लखनौर के फकीर अरफदीन ने भी इस बालक का सजदा किया था और उसे देवदूत घोषित किया था।यह बालक गोविंदराय ही थे। गोबिंद राय ने अपने जीवन के प्रारंभिक पांच वर्ष पटना में ही बिताए थे। बचपन में दूसरे बच्चों के साथ युद्ध के खेल खेलते थे एक ब्राह्मण पंडित शिवदत्त समेत उनके कई प्रशंसक थे। एक बार पटना के निःसंतान राजा फतेहचंद और उनकी पत्नी पंडित शिवदत्त के यहां गए और उनसे एक बच्चे का आशीर्वाद मांगा।शिवदत्त ने उन्हें सलाह दी कि यदि गोविंद राय जैसा निष्पाप निश्छल बच्चा उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगा तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी तब राजा और रानी ने गोविंद राय से प्रार्थना कि वे उनकी संतान प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें, यह सुनकर बालक गोविंद राय जैसी ही हो तब गोबिंद राय हल्के से मुस्कराए और बोले कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता इसलिए रानी साहिबा उन्हें ही अपना बेटा बुला सकती हैं। उस दिन से रानी उन्हें बाला प्रीतम (बाल ईश्वर) के नाम से बुलाने लगी। अब भी कहीं-कहीं गुरु गोबिंद सिंह का उद्धरण देते वक्त लोग बालाप्रीतम शब्द का प्रयोग करते हैं।

राजा रानी ने गोबिंद राय और उनके दोस्तों के लिए महल के दरवाजे खोल दिए।उनके खाने के लिए एक बड़ा हाल भी बनवाया।गोविंद राय के अन्य दो प्रशंसकों में नवाब रहीम बक्श और नवाब करीम बक्श के नाम भी शामिल हैं।नवाब करीम बक्श ने इस दैवीय बालक को एक गांव और बगीचे उपहार में दिए थे।

गुरु तेग बहादुर ने बिलासपुर (कहलूर) के राजा से जमीन खरीदकर 1665 में आनंदपुर साहिब का शिलान्यास किया था। पूर्वी भारत की यात्रा के पश्चात उन्होंने अपना परिवार आनंदपुर साहिब बुला लिया तब इस जगह को चक्क नानकी कहा जाता था शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बसे इस शहर में गोबिंद राय ने मार्च 1672 में पैर रखा उनकी प्रारंभिक शिक्षा में पंजाबी, ब्रज, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान शामिल था।साथ ही सैन्य प्रशिक्षण भी हिंदी और संस्कृत का अध्ययन पटना में शुरू किया। आनंदपुर साहिब में साहिब चंद से उन्हें पंजाबी सीखी काजी पीर मोहम्मद ने उन्हें फारसी और उर्दू का ज्ञान दिया उनके सैन्य प्रशिक्षण के लिए एक राजपूत योद्धा नियुक्त किया गया था। 1675 में कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किए जाने के खिलाफ गुरु तेग बहादुर के मुगल बादशाह औरंगजेब से बात की औरंगजेब को यह बात पसंद नहीं आई और उसने 11 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का चांदनी चौक दिल्ली में सरे बाजारसिर कलम करवा दिया। गुरु तेग बहादुर का कटा सिर प्रदर्शन के लिए चौक पर रखा जाने वाला था। गुरु की नृशंस हत्या से उनके मानने वाले डर गए।कुछ लोगों ने तो खुद को गुरु का समर्थक मानने से भी इंकार कर दिया। उन्हें डर था कि बादशाह उन्हें भी मरवा देगा। गुरु तेग बहादुर के एक सच्चे भक्त भाई जैता (भाई जीवन सिंह) ने अपने गुरु के कटे हुए सिर को नुमाइश होने से पहले ही उठाकर आनंदपुर पहुंचा दिया।गुरु तेगबहादुर ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पुत्र गोबिंदराय को अगला गुरु घोषित कर दिया था।इसलिए उनके बाद गोबिंद राय ने सिखों के दसवें गुरु का पदभार संभाला। दिल्ली में अपने पिता के साथ हुई घटना से सबक लेते हुए उन्होंने अपने समर्थकों में बलिदानी जजबात भरने का काम शुरु किया। उन्होंने 52 विद्वान कवियों को वीरता पूर्ण संस्कृत काव्यों को सरल भाषा में अनुवाद करने के काम में लगा दिया।अपने समर्थकों में युद्धोन्माद भरने के लिए अपनी कई रचनाओं में रणगीत लिखे। साथ ही उन्होंने प्रेम, समानता, एक ईश्वर की उपासना, मूर्तिपूजा के ह्रास और अंधविश्वास दूर करने वाली रचनाएं भी लिखीं। गुरु गोबिंद राय के बढ़ते प्रभाव से बिलासपुर के राजा भीमचंद को चिंता होने लगी है। आनंदपुर बिलासपुर की सीमा में ही स्थित था।इधर गुरुजी ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए रण नगाड़ा बनाने का आदेश दिया।इस तरह के जंगी नगाड़े बजाना उन दिनों सेना नायकों तक ही सीमित था। राजा ने रण नगाड़े को एक विद्रोही कदम माना।उसने गुरुजी से आनंदपुर में एक मुलाकात की। गुरु के दरबार में राजा का भव्य स्वागतकिया गया। वहां भक्तों द्वारा गुरु को अर्पण किए गए उपहारों को देखकर राजा की आंखें फटी रह गई ।बाद में भीमचंद ने गुरुजी के पास संदेश भिजवाया कि वह प्रसादी नामक हाथी पर सवारी करना चाहता है।

यह हाथी भक्तों ने गुरुजी को भेंट किया था। गुरुजी ने राजा की नीयत भांप ली कि एक बार सवारी करने के बाद राजा हाथी वापस नहीं करेगा।इसलिए उन्होंने राजा को यह कहकर हाथी देने से इंकार कर दिया कि इससे भक्त नाराज होंगे। इन सब घटनाओं से राजा और गुरुजी के बीच तनाव बढ़ता ही गया ।अप्रैल 1685 में सिरमूर के राजा मत प्रकाश के बुलावे पर गुरुजी ने अपना निवास पाओंता स्थानांतरित कर लिया। मत प्रकाश ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह के खिलाफ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गुरुजी को अपने पास बुलाया था।गुरुजी ने पौंता में अपने शिष्यों से बहुत कम समय में एक किला भी बनवा लिया।वे अपनी सैन्यशक्ति बढ़ाने में लगे रहे।

राजा फतेह शाह भी गुरु से मिलने आया। जिससे गुरुजी बड़े ही आदर के साथ मिले। गुरुजी ने दोनों राजाओं के बीच संधि करा दी।वे तीन साल तक वहीं रहे और कई रचनाएं लिखीं।पातों में रहने के दौरान भी भीमचंद और गुरुजी के बीच तनाव बढता ही गया जिसका नतीजा भानगी के युद्ध के रूप में सामने आया। गढ़वाल के राजा फतेह शाह, कटोच के किरपाल, गुलेर के गोपाल, हादुर के हरीचंद तथा जसवाल के राजा भीमचंद के साथ थे।इसके अलावा गुरू से अलग हुए उनके कुछ पठान सेवकों का भी भीमचंद को समर्थन था। गुरुजी के साथ उनके शिष्य, कुछ उदासी, कुछ पठान और सधुआरा के पीर बुधुशाह के 700 समर्थक थे। गुरुजी ने भग्न गनी का युद्ध जीत लिया। इस युद्ध को जीतने के कुछ समय बाद गुरुजी ने आनंदपुर वापस लौटने का फैसला किया। वापसी की यात्रा में गुरु जी सधुआरा, लहर पुर, रायगढ़, तबरा, रायपुर, तोदा, नादा ढाकोली, कोटला, घनौला, बंगा और कीरतपुर में भी रुके। अंततः आनंद पुर पहुंचकर उन्होंने भीमचंद से शांति समझौता किया।

1680 के आसपास दक्खन में अपने अभियान का खर्च पूरा करने के लिए औरंजेब ने पहाड़ी राजाओं से बकाया कर वसूलना शुरू कर दिया।इन राजाओं पर लगातार तीन साल का कर बाकी था।कांगड़ा और आस-पास के इलाके की वसूली आलिफ खान को सौंपी गई थी।कुछ राजाओं ने तो कर देना स्वीकार कर लिया. लेकिन भीमबंद ने शाही फरमान मानने से इंकार कर दिया। गुरुजी ने भीमबंद का साथ दिया और इसके परिणाम स्वरूप हुए नादौन के युद्ध को जीत लिया। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

1694 में पंजाब के मुगलिया सूबेदार दिलावर खान ने अपने बेटे को एक हजार सैनिकों के साथ आनंदपुर पर कब्जा करने भेजा।सतलज नदी के पास गुरु के सैनिक आलम चांद (आलम सिंह) ने खान जादे की रोका और गुरु की सेना को सतर्क कर दिया। रणजीत नगाड़ा गूंजने लगा।गुरु की सेना ने नदी की ओर कूच कर दिया। नतीजतन मुगल सेना को पीछे लौटना पड़ा।इस हार से बौखलाकर दिलावर खान ने अपने गुलाम हुसैन की अगुवाई में दो हजार सैनिक भेजे।हुसैन ने कुछ पहाड़ी राजाओं को हराकर और कुछ को अपनी ओर मिलाकर गुलेर पर कब्जा कर लिया।उसने राजा गोपाल से 10 हजार रुपए मांगे। गोपाल ने हुसैन से मध्यस्थता के लिए गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी ने अपने प्रतिनिधि संगीता को सात प्लाट्नों के साथ हुसैन के पास भेजा। पर बात नहीं बनी। बाद में युद्ध हुआ और हुसैन मारा गया।भीमचंद हुसैन का साथ दे रहा था। हुसैन के ठंडे होते ही भीमचंद की फौजें भाग खड़ी हुई।राजा गोपाल की जीत हुई।दिलावर खान ने जुझार सिंह और चंदेल राय के नेतृत्व में अपने आदमी शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ओर भेजे।उन्हें जसवाल के गजसिंह ने धूल चला दी। शिवालिक में हो रही हलचल ने औरंगजेब के कान खड़े कर दिए ,उससे अपने बेटे की कमान में फौजी दस्ते शिवालिक की तरफ भेजे।

कांतिलाल मांडोत

नीति-नेतृत्व-नियत के साथ आस्था का गठजोड़ भारत को प्रदूषण-मुक्त बना सकता है

प्रदूषण आज केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, सामाजिक संतुलन और सभ्यता के अस्तित्व की निर्णायक रेखा बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण विश्व-भर में लगभग 68 लाख असामयिक मौतें हुई, जिनमें भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से भी अधिक है। यह स्थिति किसी एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है।

विडंबना यह है कि हम पर्यावरण प्रदूषण पर पाठ्य-पुस्तकों में पढ़ते हैं, शोध संगोष्ठियों में विमर्श करते हैं, संसद में इस पर चर्चा की मांग उठाते हैं और समय-समय पर प्रदूषण-मुक्ति के संकल्प भी लेते हैं, किंतु जन-व्यवहार में वास्तविक सुधार की बात प्रायः हाशिये पर चली जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के 2024 के आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि देश के 39 प्रमुख शहरों में से 31 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ऐक्यूआई) 300 से ऊपर, अर्थात 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच चुका है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि जल, भूमि, वायु और ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधियां ही मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इसके बावजूद नागरिक, नेतृत्व और संस्थाएं प्रदूषण की आहट, उसके दुष्परिणामों और भविष्य के खतरों के प्रति प्रायः उदासीन ही दिखाई देते हैं।

पिछले कुछ दशकों में भारत में राजनेताओं, फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, धर्मगुरुओं, मीडिया एंकरों, उद्यमियों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का सामाजिक प्रभाव उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। विभिन्न सामाजिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इन प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन से संचालित जन-जागरूकता अभियानों की सफलता की संभावना 30 से 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि ये जनमानस की सोच और व्यवहार को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि ऐसी हस्तियां किसी आर्थिक या प्रचारात्मक लोभ से परे, इसे अपना सामाजिक कर्तव्य समझकर आगे आएं। कुछ लोग इस दिशा में प्रयासरत भी हैं, किंतु भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए यह संख्या अभी नगण्य है।

स्वच्छ भारत अभियान ने यह सिद्ध किया है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और जन-भागीदारी एक साथ आती हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन संभव है। उसी तर्ज पर यदि 'प्रदूषण-मुक्त भारत अभियान' को नीति, कानून और नेतृत्व के साथ जमीन पर उतारा जाए तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम पुस्तकों से निकलकर सड़कों और घरों तक पहुंचें, तो जन-व्यवहार में बदलाव निश्चित रूप से देखा जा सकता है।

भारतीय परंपरा में धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि जीवन-शैली है। ऋग्वेद का मंत्र 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' , मनुष्य को पृथ्वी का उत्तरदायी पुत्र घोषित करता है। अथर्ववेद का पृथ्वी-सूक्त पंचमहाभूतों के संतुलन को जीवन का आधार मानता है। हमारी सांस्कृतिक चेतना में नदियां माता हैं, वृक्ष देवतुल्य हैं और पर्वत आराध्य हैं। जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत केवल मानव तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त जैविक घटकों के प्रति करुणा और संरक्षण का संदेश देता है। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग अंध-उपभोग और संसाधनों के अति दोहन से विरत रहने की प्रेरणा देता है। सिख धर्म में गुरु नानक देव का वचन 'पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत' , पर्यावरण को परिवार का अंग मानकर उसके प्रति जिम्मेदार आचरण की सीख देता है। इस्लाम में पृथ्वी को अल्लाह की अमानत (कुरान) कहा गया है, जबकि ईसाई परंपरा में सृष्टि-रक्षा को ईश्वर-सेवा का स्वरूप माना गया है। स्पष्ट है कि सभी प्रमुख धर्मों में पर्यावरण-अनुकूल आचरण के स्पष्ट संदेश मौजूद हैं। इसके बावजूद, धार्मिक आस्थाओं और दैनिक व्यवहार के बीच एक गहरी खाई दिखाई देती है। आज आवश्यकता है कि सभी धर्मों के धर्मगुरु अपने प्रवचनों, आयोजनों और सार्वजनिक संवादों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल-संरक्षण और वृक्षारोपण को अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दें। यदि आस्था के मंच से यह संदेश स्पष्ट रूप से जाए कि मानवजनित प्रदूषण न केवल प्रकृति के विरुद्ध है, बल्कि धार्मिक मूल्यों के भी प्रतिकूल है, तो उसका प्रभाव व्यापक और स्थायी हो सकता है।

हमें अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) की वर्ष 2023 की चेतावनी को भी गंभीरता से लेना चाहिए, जिसके अनुसार प्रदूषण और जलवायु संकट को नियंत्रित न किया गया तो वर्ष 2050 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 2.8 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। इसके अतिरिक्त, करोड़ों लोग प्रदूषण-जनित गंभीर बीमारियों, असमय मृत्यु और जीवन-गुणवत्ता में गिरावट का शिकार हो सकते हैं। वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाली क्षति की भरपाई तो संभव ही नहीं होगी।

अतः यह समय मात्र चिंता व्यक्त करने का नहीं, बल्कि निर्णायक और सामूहिक कार्रवाई का है। यदि नीति-निर्माताओं की स्पष्ट दिशा, नेतृत्व की ईमानदार पहल, प्रशासन की सख्ती और आस्था की नैतिक शक्ति तथा जन-मानस का सहयोग एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो प्रदूषण-मुक्त भारत का सपना केवल नारा नहीं, बल्कि साकार वास्तविकता बन सकता है।

डा मनमोहन प्रकाश

किसान दिवसरूस्मरण नहीं आत्ममंथन का दिन

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है यह कथन वर्षों से दोहराया जाता रहा हैए किंतु व्यवहार में गाँव और किसान अक्सर नीति.निर्माण की हाशिये पर रहे हैं। कृषि आज भी देश की बड़ी आबादी का जीवनाधार है परंतु यह भी उतना ही सच है कि यही क्षेत्र सबसे अधिक असुरक्षा अनिश्चितता और संकट से घिरा हुआ है। ऐसे परिदृश्य में किसान दिवस हमें आत्ममंथन के लिए बाध्य करता हैए क्या हमने उस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाया हैए जो अन्नदाता के प्रति हमारी है

23 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय किसान दिवस केवल एक तिथि या औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के उस मूल प्रश्न की याद दिलाता है कि क्या देश का अन्नदाता आज भी वही सम्मान और सुरक्षा पा रहा है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता के समय की गई थी। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती से जुड़ा है एक ऐसे नेता की स्मृति से जिन्होंने राजनीति को सत्ता का खेल नहींए बल्कि समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की आवाज़ बनाने का माध्यम समझा। किसान दिवस दरअसल उस विचारधारा का प्रतीक हैए जिसमें खेतए किसान और गाँव को राष्ट्र निर्माण की केंद्रीय धुरी माना गया। चौधरी चरण सिंह का जीवन और राजनीति इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास थी। किसान परिवार में जन्मे चरण सिंह ने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को नीतिगत बहस का विषय बनाया। उनके लिए किसान कोई भावनात्मक प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक इकाई था। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी के बाद के भारत तकए वे लगातार इस बात पर बल देते रहे कि यदि कृषि और ग्रामीण समाज को मजबूत नहीं किया गयाए तो देश की प्रगति खोखली रह जाएगी। यही कारण है कि वे औद्योगीकरण के विरोधी नहीं थेए परंतु कृषि की कीमत पर होने वाले विकास के सख्त आलोचक थे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि.केंद्रित सोच तकए चौधरी चरण सिंह ने यह स्पष्ट किया कि जो खेत जोतता हैए उसी का उस पर अधिकार होना चाहिए। यह विचार केवल भूमि स्वामित्व का नहींए बल्कि किसान के आत्मसम्मान का प्रश्न था। उन्होंने राजनीति में रहते हुए बार.बार चेताया कि यदि किसान को केवल उत्पादन का साधन बनाकर देखा गयाए तो सामाजिक असंतोष और आर्थिक असमानता गहराती जाएगी। दुर्भाग्य सेए समय ने उनके इस भय को कई बार सच साबित किया है। आज जब हम किसान दिवस मनाते हैं तो सामने एक जटिल यथार्थ खड़ा है। जलवायु परिवर्तन ने खेती को अनिश्चित बना दिया हैए लागत लगातार बढ़ रही है ज़मीन का विखंडन हो रहा है और बाज़ार में किसान की सौदेबाज़ी की शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्यए फ़सल बीमाए सिंचाई और कर्ज़ जैसे मुद्दे केवल तकनीकी या आर्थिक प्रश्न नहीं हैं बल्कि किसान के जीवन और भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में किसान दिवस को केवल श्रद्धांजलि तक सीमित रखनाए उसके वास्तविक अर्थ को कमज़ोर कर देता है। चौधरी चरण सिंह का आग्रह था कि किसान को नीति.निर्माण की प्रक्रिया का सहभागी बनाया जाए। यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक तकनीक डिजिटल खेतीए कृषि नवाचार और वैश्विक बाज़ार की बातें तभी सार्थक होंगीए जब किसान को इनके केंद्र में रखा जाएगा। यदि नीतियाँ कागज़ पर तो प्रगतिशील होंए पर ज़मीन पर किसान असुरक्षित रहे तो वह विकास टिकाऊ नहीं हो सकता।

महेन्द्र तिवारी

संपादकीय

एक्सप्रेस वे पर लोगों को चलना सिखाना होगा

विकास की रफ़्तार तभी सुखद है जब वह सुरक्षित हो। भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, विशेषकर सड़क तंत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, वे अभूतपूर्व हैं। जहाँ पहले दो शहरों के बीच का सफर घंटों और दिनों में तय होता था, आज वह समय काफी कम हो गया है। लेकिन इस भौतिक प्रगति के बीच एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। क्या हम इन आधुनिक सड़कों पर चलने के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार हैं? अब समय आ गया है कि हम ईंट और डामर की सड़कों से आगे बढ़कर 'मानव व्यवहार' में सुधार पर निवेश करें। याद रखिए, एक्सप्रेसवे केवल मंजिल तक जल्दी पहुँचने के लिए नहीं हैं, बल्कि सुरक्षित पहुँचने के लिए हैं। यदि हम गति के साथ गरिमा और अनुशासन नहीं अपना सकते, तो ये चमचमाती सड़कें हमारे लिए वरदान के बजाय अभिशाप सिद्ध होंगी। अब जरूरत है कि 'हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने से पहले लोगों को उन पर चलना सिखाना चाहिए '–यह केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि समय की मांग है। केवल कंक्रीट के जाल बिछाने से राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा, बल्कि उन सड़कों पर सुरक्षित सफर सुनिश्चित करना भी सरकार और नागरिक दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

भारत में सड़क निर्माण की गति पिछले दस वर्षों (2014-2024) में सांख्यिकीय और भौगोलिक दोनों दृष्टि से ऐतिहासिक रही है। 2014 के आसपास देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 91,287 किलोमीटर थी, जो 2024 तक बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। 2014-15 में सड़क निर्माण की दर लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो वर्तमान में बढ़कर औसतन 28 से 37 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुँच चुकी है। भारत ने 'भारतमाला परियोजना' के तहत विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे गलियारे भारत की नई पहचान बन चुके हैं। अटल टनल और चेनाब ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार इसी दशक की देन हैं, जिन्होंने दुर्गम क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा है। इतना सब हुआ। सड़कों की चौड़ाई तो बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर हम अब भी संघर्ष कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि हमारी लापरवाही की कीमत बहुत भारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में हुई 4,49,002 दुर्घटनाओं 1,51,113मौत हुई। 2020 में हुई 3,66,138 दुर्घटनाओं में 1,31,714 व्यक्ति मरे। 2021 में हुए 4,12,432 एक्सीडेंट में 1,53,972 व्यक्ति मौत के मुंह में समा गए। 2022 में हुई 4,61,312 दुर्घटनाओं मे 1,68,491 जान गई। 2023 हुई 4,80,000+ (अनुमानित) में 1,70,000 व्यक्ति मौत के शिकार हुए। ये आंकड़े बताते है कि दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। घायलों की संख्या तो मरने वालों से काफी ज्यादा होनी चाहिए। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 19 लोग मरे। 100 से ज्यादा घायल हुए।

आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लगभग 70 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं 'ओवरस्पीडिंग' यानी अत्यधिक गति के कारण होती हैं। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं की गंभीरता सामान्य सड़कों से कहीं अधिक होती है क्योंकि यहाँ वाहनों की गति बहुत तेज़ होती है। एक्सप्रेसवे सामान्य सड़कें नहीं हैं। यहाँ ड्राइविंग के अपने नियम हैं, जिन्हें भारतीय चालकों को सीखना होगा। इन पर चलते समय लेन का अनुशासन का पालन करना होगा । भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग भारी वाहन सबसे दाई ओर चलाते हैं, जबकि वह लेन केवल ओवरटेकिंग के लिए होती है। तेज़ रफ़्तार वाली सड़कों पर गलत लेन में वाहन चलाना आत्महत्या के समान है।

एक्सप्रेसवे पर केवल अधिकतम गति ही नहीं, बल्कि न्यूनतम गति का पालन भी जरूरी है। धीमी गति से चल रहे वाहन तेज़ रफ्तार वाहनों के लिए अवरोध बन जाते हैं, जिससे टक्कर की संभावना बढ़ जाती है। एक्सप्रेसवे की सीमेंट वाली सड़कों पर टायर बहुत जल्दी गर्म होते हैं। यदि टायर पुराने या घिसे हुए हैं, तो वे फट सकते हैं। लोगों को यह सिखाना जरूरी है कि लंबी यात्रा से पहले अपने वाहनों की तकनीकी जांच कैसे करें। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए बने रास्तों (रैम्प) का सही उपयोग करना अधिकांश लोगों को नहीं आता। अचानक मुख्य मार्ग पर वाहन मोड़ देना घातक होता है।

वाहनों की संख्या और लाइसेंस धारकों के बीच का यह अंतर यह दर्शाता है कि हमारी सड़कों पर 'अकुशल' चालकों की फौज मौजूद है। एक्सप्रेसवे जैसी तेज़ रफ़्तार वाली सड़कों पर यह स्थिति और भी घातक हो जाती है। एक आदर्श स्थिति में, सड़क पर चल रहे हर वाहन के अनुरूप कम से कम एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। हालांकि, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार, देश में कुल ड्राइविंग लाइसेंसों की संख्या लगभग 21 से 23 करोड़ के बीच है। यदि हम 35 करोड़ पंजीकृत वाहनों की तुलना 23 करोड़ लाइसेंसों से करें, तो स्पष्ट होता है कि वाहनों और चालकों के बीच 12 करोड़ का भारी अंतर है। विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) और पुलिस द्वारा चलाए गए जांच अभियानों के अनुसार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक अनुमान के अनुसार, देश में लगभग 25से 30 प्रतिशत लोग बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन चला रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हादसों में जान गंवाने वाले या दोषी पाए जाने वाले चालकों में से लगभग 65 प्रतिशत युवाओं के पास वैध लाइसेंस नहीं होता। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत और भी अधिक है, जहाँ लगभग 40 प्रतिशत दोपहिया चालक बिना लाइसेंस के गाड़ी दौड़ा रहे हैं। एक पुरानी रिपोर्ट (सेव लाइफ फाउंडेशन) यह भी बताती है कि जिनके पास लाइसेंस है, उनमें से भी 10 में से छह लोगों ने बिना किसी व्यावहारिक ड्राइविंग टेस्ट के इसे प्राप्त किया है, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा है।

इसलिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाने पर केवल जुर्माना नहीं, बल्कि वाहन को लंबे समय के लिए ज़ब्त करना होगा। नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने पर अभिभावकों को जेल की सजा का प्रावधान में कड़ाई जरूरी है। डिजिटल तकनीक का उपयोग कर हर मोड़ पर बिना लाइसेंस वाले पर कार्रवाई अमल में लानी होगी।

इन एक्सप्रेसवे पर चलना सिखाने के लिए सिर्फ शिक्षा पर्याप्त नहीं है; अनुशासन के लिए कानून का भय भी आवश्यक है। गलत वाहन चलाने वालों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और उल्टी दिशा (रॉन्ग साइड) में चलने वालों पर इतनी सख्ती होनी चाहिए कि वे दोबारा नियम तोड़ने की हिम्मत न करें। बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाना चाहिए। हर कुछ किलोमीटर पर कैमरे और रडार होने चाहिए जो नियम तोड़ते ही चालान सीधे चालक के पते पर भेजें। नियम पन मानने वालों पर जुर्माना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दंडात्मक होना चाहिए ताकि वह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाले।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक किलोमीटर पर कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। यह तो पूरे देश के महत्वपूर्ण मार्ग पर करना होगा, तभी दुर्घटनाएं रूकेंगी। सड़क सुरक्षा को केवल पुलिस का विषय न मानकर इसे शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा। विद्यालयों में बच्चों को बचपन से ही सड़क के संकेतों, लेन अनुशासन और जीवन के मूल्य के बारे में सिखाया जाना चाहिए। जब तक सुरक्षा की भावना हमारे संस्कार में नहीं आएगी, तब तक आधुनिक सड़कें केवल मृत्यु के गलियारे बनी रहेंगी।

अशोक मधुप

राष्ट्रवाद का बदलता स्वरूप सत्ता के चाहत की अभिलाषा

राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण, सत्ता, भीड़ और लोकतंत्र के बीच राष्ट्रीयता।

वर्तमान समय में राष्ट्रवाद अपने सबसे जटिल, विरोधाभासी और बहुअर्थी दौर से गुजर रहा है, यह वह राष्ट्रवाद नहीं रह गया है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान त्याग, नैतिक साहस, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समरसता का प्रतीक था, बल्कि यह एक ऐसा राष्ट्रवाद बनता जा रहा है जिसे बार-बार सत्ता की भाषा में परिभाषित किया जा रहा है, आज राष्ट्र सरकार का पर्याय बनने की ओर अग्रसर है और सरकार की आलोचना को राष्ट्रविरोध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यही वह बिंदु है जहाँ राष्ट्रवाद अपनी आत्मा खोने लगता है और लोकतंत्र अपने आधार, आज जब चुनावी सभाओं, टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया मंचों पर राष्ट्रवाद को धर्म, जाति, सैन्य शक्ति और भावनात्मक उन्माद के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, तब यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि क्या राष्ट्र प्रेम का अर्थ केवल सत्ता के समर्थन तक सीमित रह गया है, हाल के वर्षों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि आतंकी घटनाओं, सीमा विवादों, सैन्य अभियानों और ऐतिहासिक स्मृतियों का चयनित उपयोग कर भावनात्मक ध्रुवीकरण को तेज किया गया है, असहमति को राष्ट्रद्रोह, प्रश्न को साजिश और आलोचना को देश के खिलाफ खड़े होने का प्रमाण बताया गया है, यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्रों के भीतर उभरते अति राष्ट्रवाद का साझा संकट है, अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास, रूस में सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद, चीन में सर्वव्यापी राज्य और एशिया व अफ्रीका में सैन्य प्रभुत्व की राजनीति यह संकेत देती है कि राष्ट्रवाद अब नागरिकों को सशक्त करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने का माध्यम बनता जा रहा है, भारत जैसे विविधता से भरे समाज में यह परिवर्तन और भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ राष्ट्र का अर्थ बहुलता, सहअस्तित्व और संवैधानिक संतुलन से जुड़ा रहा है, किंतु वर्तमान राजनीतिक विमर्श में बहुलता को कमजोरी और असहमति को बाधा के रूप में चित्रित किया जा रहा है, सत्ता की निरंतरता के लिए जातिगत समीकरणों का सूक्ष्म लेकिन आक्रामक उपयोग, धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण और लोकलुभावन योजनाओं की होड़ लोकतंत्र को तात्कालिक लाभ की राजनीति में कैद कर रही है, मुफ्त उपहार, नकद हस्तांतरण और प्रतीकात्मक घोषणाएँ जनता को क्षणिक संतोष तो देती हैं लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक अनुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्थागत सुधार जैसे मूल प्रश्नों को हाशिए पर धकेल देती हैं, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति माना जाता है, किंतु आज सत्ता को स्थायित्व और राष्ट्रहित को सत्ता की निरंतरता से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को वैधता मिलने लगती है, हाल के वर्षों में दलबदल की बढ़ती घटनाएँ, विचारधारा से अधिक सत्ता की प्राथमिकता और राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का क्षरण यह दर्शाता है कि राजनीति सिद्धांत से नहीं बल्कि अवसर से संचालित हो रही है, जातिवादी मतदान और पहचान आधारित ध्रुवीकरण के कारण खाप पंचायतों जैसी समानांतर सत्ता संरचनाएँ पुनः सामाजिक स्वीकृति पाने लगी हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के संवैधानिक आदर्शों के बावजूद धार्मिक आस्थाओं के नाम पर नीतिगत हस्तक्षेप और व्यक्तिगत जीवनशैली पर नियंत्रण यह प्रश्न उठाता है कि राष्ट्रवाद कहीं नागरिक स्वतंत्रताओं का शत्रु तो नहीं बनता जा रहा, पशु व्यापार, भोजन की पसंद और सांस्कृतिक व्यवहार जैसे विषय जब राज्य के नियंत्रण का विषय बनते हैं तब लोकतंत्र का स्वरूप धीरे-धीरे नैतिक निगरानी में बदलने लगता है, अति राष्ट्रवाद का सबसे खतरनाक पक्ष यह है कि वह भय पैदा करता है, भय बाहरी शत्रु का, भय आंतरिक दुश्मन का और भय असहमति का, और भय जब राजनीति का आधार बनता है तब लोकतंत्र केवल चुनावी औपचारिकता बनकर रह जाता है, इतिहास साक्षी है कि बीसवीं सदी में जर्मनी, इटली और स्पेन में इसी भय आधारित राष्ट्रवाद ने फासीवाद को जन्म दिया, एशिया में पाकिस्तान, म्यांमार और उत्तर कोरिया में सुरक्षा और राष्ट्ररक्षा के नाम पर सैन्य प्रभुत्व लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करता रहा है, भारत में भी यदि राष्ट्रवाद को केवल सैन्य शक्ति, बहुमत की भावना और नेता-केंद्रित आस्था से जोड़ा गया तो यह संविधान द्वारा प्रदत्त संतुलन को कमजोर करेगा, लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, संस्थाओं की स्वायत्तता और कानून के समक्ष समानता का नाम है, किंतु वर्तमान विमर्श में बहुमत को अंतिम सत्य और संख्या को नैतिक वैधता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, मीडिया के एक बड़े हिस्से द्वारा सत्ता समर्थक राष्ट्रवादी नैरेटिव का प्रसार, सोशल मीडिया पर ट्रोल संस्कृति और चयनित सूचना का उग्र प्रसार लोकतांत्रिक संवाद को संकीर्ण और आक्रामक बना रहा है, ऐसे समय में सिविल सोसाइटी, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और न्यायिक संस्थाओं की भूमिका निर्णायक हो जाती है, यदि यह वर्ग चुप रहता है तो लोकतंत्र धीरे-धीरे आत्मसमर्पण कर देगा, राष्ट्रवाद का पुनर्पाठ आवश्यक है जहाँ राष्ट्र सरकार से बड़ा हो, संविधान सत्ता से ऊपर हो और नागरिक की गरिमा सर्वोपरि मानी जाए, राष्ट्र प्रेम का अर्थ प्रश्न करना, जवाबदेही माँगना और संस्थाओं को मजबूत करना भी होना चाहिए, न कि केवल नारे लगाना और भीड़ का हिस्सा बन जाना, तात्कालिक लोकप्रियता, भावनात्मक ध्रुवीकरण और सत्ता लोलुपता के स्थान पर दीर्घकालिक नीतिगत दूरदर्शिता, सामाजिक संतुलन और संवैधानिक नैतिकता को केंद्र में लाना ही लोकतंत्र को बचा सकता है, अन्यथा राष्ट्रवाद का यह बदला हुआ रूप राष्ट्र को जोड़ने के बजाय उसे भीतर से खोखला करता चला जाएगा और इतिहास एक बार फिर हमें चेतावनी देगा कि लोकतंत्र का पतन अचानक नहीं बल्कि तालियों, नारों और मौन के बीच धीरे-धीरे होता है।

संजीव ठाकुर

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। नोटः–उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

अधिकारियों व ग्राम प्रधानों की मिली भगत के चलते गांवो में कराए जा रहे मानक विहीन कार्य

बिसवां- सीतापुर जहां एक ओर शासन व प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास खंड के अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की कथित मिलीभगत के चलते गांवों में मानकविहीन कार्य कराए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कदूनी के शंकरपुर गांव में सामने आया है। यहां ग्राम प्रधान द्वारा खड़ंजा निर्माण में खुलेआम पीली ईंटों का उपयोग किया जा गया है। इतना ही नहीं, नाली निर्माण में भी मानकों की अनदेखी करते हुए पीली ईंटों से कार्य कराया गया है। इस अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध मेंखंड विकासअधिकारी बिसवां से वार्ता किए जाने पर उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रोडवेज कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी पहल, निगम परिसर में लगा बहुआयामी स्वास्थ्य जांच शिविर

बलरामपुर। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने वाले रोडवेज कर्मियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम परिसर में बहुआयामी सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ड्राइवर, कंडक्टर, कार्यालय एवं वर्कशॉप कर्मचारियों ने सहभागिता कर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। शिविर का उद्घाटन जिला क्षय रोग अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों का स्वस्थ रहना न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।स्वास्थ्य शिविर में नेत्र परीक्षण, सामान्य रक्त जांच, एचआईवी परामर्श एवं जांच, टीबी स्क्रीनिंग तथा एसटीआई परामर्श एवं जांच जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। जांच के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न बीमारियों से बचाव, समय पर जांच तथा उपचार के महत्व के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।

पलिया क्षेत्र में अनोखी घटना

गाय ने एक साथ दो बच्चों को दिया जन्म, देखने उमड़ी लोगों की भीड़

पलिया- पलिया क्षेत्र के ग्राम बोझवा में एक दुर्लभ और सुखद घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। गांव निवासी जयेन्द्र सिंह की गाय ने एक साथ दो स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। इनमें एक बछड़ा और एक बछिया शामिल हैं। गाय द्वारा जुड़वा बच्चों को जन्म देने की खबर फैलते ही ग्रामीणों और आसपास के लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए जुटने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिलती है, इसी कारण यह पूरे क्षेत्र में खास चर्चा का विषय बनी हुई है। परिजनों के अनुसार गाय और दोनों नवजात बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। गांव के लोग इसे शुभ संकेत मान रहे हैं और परिवार को बधाइयाँ दे रहे हैं। यह अनोखी घटना न सिर्फ ग्राम बोझवा बल्कि पूरे पलिया क्षेत्र में कौतूहल और उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी ज्यादा असरदार हेडलाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, या अखबार कटिंग स्टाइल में भी तैयार कर सकता हूँ।

सूचना

मेरे पिता त्रिवेनी यादव पुत्र गोरे यादव की मृत्यु दिनांक 16/11/2007 को हो गई थी मृत्यु पंजीकरण न हो पाने के कारण वरासत व अन्य महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गये थे प्रार्थी काफी दिनों तक बाहर था अब घर वापस आ गया है मृत्यु पंजीकरण आवश्यक है

विक्रम यादव पुत्र
स्व. त्रिवेनी यादव
ग्राम मदरहवा कला विकास खंड
पचपेड़वा परगना/ तहसील तुलसीपुर
जनपद बलरामपुर
मो.-8081321883

भ्रष्टाचारियों के सीने पर लगातार लोट रहे सांप

●राजा की कार्रवाई से प्रजा में खुशी तो भ्रष्टाचारियों में दहशत का माहौल

कड़ाके की ठंड में लगातार छूट रहा भ्रष्टाचारियों का पसीना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर- जनपद सीतापुर में जहां फाइलें धूल में दबकर सो रही थी माफिया, दलालों, भ्रष्टाचारियों का जंगल राज चलता था लेकिन कहते हैं अंधेरा जितना ज्यादा होता है रोशनी भी उतनी ही तेज आती है सीतापुर में भी एक ऐसी रोशनी उतरी है सुपर हीरो की तरह यह कोई सीन नहीं यह सीतापुर की हकीकत है राजा गणपति आर की गाड़ियां देखकर भ्रष्टाचारियो के सीने पर सांप लोट जाते है। सर्दियों में भी माफियाओं के पसीने छूट रहे हैं अब सीतापुर में गुंडागर्दी का डर नहीं नियम कानून की गूंज सुनाई देती है। जो फाइलें सालों से अलमारी में धूल खा रही थी लोगों की उम्मीदें जमी पड़ी थी फिर से हरकत में आ गई है। एक अफसर ने सिस्टम की सांस खोल दी टेबल पर फाइल आते ही अधिकारियों की धड़कनें तेज हो जाती है क्योंकि जुगाड़ नहीं जांच और जिम्मेदारी चलती है। शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य नीति हो, बिजली विभाग हो, निजी हो या सरकारी कोई भी संस्थान या कार्यालय किसी को नहीं पता डीएम कब और कहां किस रूप में पहुंच जाए। कभी अंधेरे में अस्पतालों अन्य संस्थानो का निरीक्षण और सुबह स्कूलों में अध्यापकों का अटेंडेंस चेक करते डीएम दिख जाते हैं तो कभी खेत में खड़े होकर किसानों की समस्याएं तो कभी विकासखंड में बैठक कर अधिकारियों की कमियों को गिना रहे होते हैं और ऑन द स्पॉट एक्शन ऐसे करते हैं जैसे साउथ इंडियन मूवी का क्लाइमेक्स यह असल जिंदगी में है डीएम कहते नहीं दिखाते हैं काम कैसे होता है कई सालों से दर्द दवाई लोग चुप बैठे-बैठे थक गए थे जिनकी आवाज फाइलों के नीचे दबी थी आज डीएम ऑफिस के बाहर लोग लंबी कतार में खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है यहां सुना भी जाएगा और किया भी जाएगा जनता का भरोसा लौट आया है और भरोसा लौट आए तभी तो सिस्टम बदलना शुरू होता है जिलाधिकारी महोदय को पता है अधिकारी अगर ड्यूटी निभा दे तो पूरा सिस्टम पूरा जिला एक नई दिशा पकड़ लेगा। सीतापुर बदल रहा है उनका सुपर हीरो अपना काम कर रहा है!!

परिवहन निगम से हुई दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों की मजिस्ट्रियल जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट लालगंज नामित

प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने बताया है कि परिवहन निगम से हुई दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों की जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट लालगंज को नामित किया गया है जो घटना घटित होने की परिस्थितियों व सम्बन्धित सभी लोगों के अभिकथन व साक्ष्य लेकर समस्त पहलुओ की गहनता से सघन जांच करके अपनी विस्तृत आख्या 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायेगें। उन्होने बताया है कि 24 अगस्त को ग्राम तिना चितरी कालेज थाना क्षेत्र लीलापुर में बस संख्या यूपी 33एटी-1897 से पूजा वर्मा पत्नी उमेश वर्मा तथा दिनांक 30 अगस्त को कैथोला रानीगंज थाना क्षेत्र लालगंज में बस संख्या-यूपी 78जेएन-2035 से सूरत सरोज पुत्र बबलू सरोज की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी।

मलिहाबाद में शर्मनाक वारदात, बच्ची से अश्लील हरकत के आरोप में इरफान उर्फ पप्पू गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद। मलिहाबाद क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत और दरिंदगी के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहल्ले के ही रहने वाले आरोपी इरफान अली उर्फ पप्पू ने बच्ची को 10 रुपये का लालच देकर अपने कमरे में बंधक बना लिया। बताया गया कि शनिवार 20 दिसंबर को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी इरफान अली उर्फ पप्पू उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो मां उसे ढूंढते हुए आरोपी के कमरे तक पहुंची। मां के आवाज लगाने पर बच्ची ने दरवाजा खोला, तभी आरोपी पप्पू पैंट की चैन बंद करते हुए मौके से फरार हो गया। बच्ची ने मां को बताया कि आरोपी पहले भी उसे पैसों का लालच देकर कमरे में बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू के खिलाफ संबंधित धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस टीमों ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में सांसद का उपवास सत्याग्रह, राकेश राठौर बोले- गांधी की विचारधारा की हत्या कर रही भाजपा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर में मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन योजना किए जाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने उपवास सत्याग्रह किया इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शहर में पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और मनरेगा का नाम यथावत रखने की मांग की। पैदल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ अम्बेडकर पार्क पहुंचा। इससे पहले सांसद राकेश राठौर ने महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अम्बेडकर पार्क में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने उपवास सत्याग्रह प्रारंभ किया सांसद राठौर ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना का नाम बदलना निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है यह फैसला उस विचारधारा पर हमला है, जिसने गरीबों, मजदूरों और वंचितों को आत्मसम्मान के साथ रोजगार का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गांधीजी के विचारों और सिद्धांतों का प्रतीक है। सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा पहले गांधी की हत्या कराने वाली विचारधारा से जुड़ी रही है और अब उनके विचारों की हत्या कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार को गांधी के नाम और उनके सिद्धांतों से समस्या है, इसलिए योजनाओं से उनका नाम हटाया जा रहा है। राम के नाम को लेकर उठे सवालों पर सांसद राठौर ने स्पष्ट किया कि भगवान राम के नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि गांधी के नाम को योजनाओं से हटाया जा रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा को विकास और रोजगार जैसे मूल मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, न कि योजनाओं के नाम बदलकर जनता का ध्यान भटकाना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे सभी ने एक स्वर में मनरेगा का नाम बहाल करने और केंद्र सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की!!

घने कोहरे में विजिबिलिटी महज 5 मीटर तक सिमट कर रह गई, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर- जनपद सीतापुर में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। रविवार के बाद सोमवार को भी सुबह से ही जिले में घने कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर विजिबिलिटी महज 5 मीटर तक सिमट कर रह गई। कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और रफ्तार पर पूरी तरह से लगाम लग गई। आज सुबह जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो ठंड के तीखे तेवरों को दर्शाता है वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था सुबह से चल रही ठंडी हवाओं ने ठिठुरन को और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे लोग गर्म कपड़ों में भी ठंड से बचाव करते नजर आए घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ तौर पर देखने को मिला। कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे की देरी से चल रही हैं यात्रियों को स्टेशन पर ठंड और कोहरे के बीच लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं कोहरे और शीतलहर के कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, कामकाजी लोगों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए वहीं हाईवे और प्रमुख मार्गों पर फॉग लाइट और डिपर का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलते दिखे। प्रशासन और यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों से सतर्कता बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है शीतलहर के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं!!

महिला का नकाब खींचने के खिलाफ ऐपवा ने निकाला मुख्यमंत्री के खिलाफ जुलूस

● ऐपवा जिलाध्यक्ष रामावती देवी ने किया सभा को संबोधित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोपालगंज- भोरे- नकाब खींचने वाले मुख्यमंत्री महिला डाक्टर से माफ़ी मांगों,धार्मिक पहचान पर हमला बंद करो, सार्वजनिक तौर पर किसी स्त्री के कपड़े खींचना मर्यादा और इंसाफ का उलंघन हैं हिन्दू- मुस्लिम महिलाओं पहनावा जिंदाबाद इत्यादि नारे लगाते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत ऐपवा ने भोरे पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला तथा भोरे चारमुहानी पर सभा की सभा को संबोधित करते हुए ऐपवा जिलाध्यक्ष सीता पाल ने कहा कि आप सब लोग फेसबुक अखबार के माध्यम से जानते है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर को प्रशस्तिपत्र देते समय सार्वजनिक रूप से उनका हिजाब खींचकर अपमानित किया गया आज इस मार्च के माध्यम से मैं इस घटना की तीखी शब्दों में निंदा करती हूँ तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने की मांग करती हूँ उन्होंने कहा कि बिहार में अगर छोटी-छोटी बच्चियों के साथ अगर बलात्कार हो रहे हैं अपराध बढ़ रहा हैं तो उसका वजह यही हैं, आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने लड़का- लड़की के बारे में कितनी शर्मिंदगी वाली क्या-क्या बात कहें हैं सब लोग जानते हैं इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया हैं, सभा को संबोधित करते हुए ऐपवा के जिलाध्यक्ष रामावती देवी -प्रभावती देवी ने कहा कि नीतीश -मोदी सरकार ने दस-दस हज़ार रुपया देकर लोगों को ठग लिया और जब सरकार बन गयी तो गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रहीं हैं उन्होंने कहा कि भोरे में गरीबों की दुकान तो उजाड़ दी गई मगर रोड के किनारे बिजली के खम्बे गड़े हैं जो जाम के गम्भीर कारण बने हुए हैं उन्होंने उन खम्भों को तत्काल हटाने व गरीबों के झोपड़ियों पर चल रहे बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग कि, सभा को जिला पार्षद सदस्य ललिता चौहान, काजल तिवारी, भोरे मुखिया प्रियंका कुमारी, गिरजा देवी इत्यादि ने संबोधित किया

युवक पर धारदार हथियार से किया ताबड़तोड़ हमला सिर-गले पर गहरे जख्म, हालत गंभीर लखनऊ रेफर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर- जनपद सीतापुर में रविवार दे रात एक युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मरणासन्न अवस्था में खेत में फेंक देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है हमलावर युवक को गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए। होश में आने के बाद घायल किसी तरह अपने घर पहुंचा, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना थाना रामकोट क्षेत्र के खटकरी खुर्द गांव की है बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ओमकार को आरोपियों ने घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद खेत में ले जाकर उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया हमलावरों ने युवक के सिर पर कई बार वार किए, उसका कान काट दिया और गला भी काटने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल युवक को मृत समझकर हमलावर खेत में ही फेंक कर फरार हो गए कुछ समय बाद होश में आने पर युवक किसी तरह खुद को घसीटते हुए घर पहुंचा। परिजन उसे इस हालत में देखकर दहशत में आ गए और तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए लखनऊ के लिए रेफर कर दिया पीड़ित के परिजनों ने शीर्ष के देवगनपुर के ग्राम प्रधान महेश पर घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है पुलिस का कहना है कि पीड़ित के बयान और परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है!!

प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे दिन दर्शकों को देखने को मिले रोमांचक मुकाबले

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां- सीतापुर मेला हजरत गुलजार शाह रह0 अलैह के हॉकी ग्राउंड में आयोजित प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे दिन दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। टूर्नामेंट के तहत कुल चार मैच खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। पहला मुकाबला शाहजहांपुर और रायबरेली के बीच खेला गया, जिसमें रायबरेली की टीम ने एकतरफा खेल दिखाते हुए 4-0 से जीत दर्ज की। रायबरेली की ओर से आकाश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा मैच बहराइच और लखीमपुर के बीच हुआ। लखीमपुर की टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 5 गोल किए, जबकि बहराइच की टीम केवल एक गोल ही कर सकी। इस प्रकार लखीमपुर ने 5-1 से मुकाबला अपने नाम किया। लखीमपुर के शैजल ने हैट्रिक लगाकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया। तीसरा मुकाबला बिसवां और बाराबंकी के बीच खेला गया, जो बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित समय तक मैच ड्रा रहा। इसके बाद शूटआउट में बिसवां की टीम ने 2 गोल किए, जबकि बाराबंकी ने 3 गोल दागकर जीत हासिल की। बाराबंकी टीम के कप्तान इब्राहीम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। चौथा मैच बरेली और शिवगढ़ के मध्य खेला गया, जिसमें शिवगढ़ की टीम ने बरेली को 2-0 से पराजित किया। टूर्नामेंट में निर्णायक की भूमिका परवेज अख्तर, मनीष द्विवेदी, खुर्शीद अहमद, फहद खान और दुर्गा प्रसाद ने निभाई। इस अवसर पर

टूर्नामेंट सचिव मास्टर असलम सहित इशरत अली, हाजी इसरार खां, राजकुमार रस्तोगी, जैनुल आबदीन, शुऐब खान, रेहान कादरी, नुसरत अली, अन्नू तथा बड़ी संख्या में खेल प्रेमी दर्शक मौजूद रहे।

विकसित भारत-जी राम जी बिल 2025 को लेकर कार्मिक हितों की आवाज, केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान से गोरखपुर मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट

●कार्मिकों के हितों के संरक्षण, मानदेय वृद्धि और सुरक्षा की गारंटी पर रखे गए ठोस सुझाव, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक प्रस्ताव पहुंचाने का मिला आश्वासन।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। विकसित भारत-जी राम जी बिल 2025 के माध्यम से कार्मिकों के हितों के संरक्षण तथा उनकी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने की मांग को लेकर सोमवार को गोरखपुर मंडल के साथियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास, भारत सरकार कमलेश पासवान से भेंट कर अपना पक्ष मजबूती से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि यह बिल कार्मिकों के अधिकारों, कार्यसुरक्षा, सेवा शर्तों तथा सामाजिक सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से मनरेगा कर्मियों के लंबे समय से लंबित मानदेय वृद्धि के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। साथ ही यह भी मांग रखी गई कि मनरेगा सहित ग्रामीण विकास योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा की गारंटी, दुर्घटना बीमा, समयबद्ध भुगतान और प्रशासनिक उत्पीड़न से संरक्षण दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि सीमित मानदेय और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों के बावजूद ये कार्मिक ग्रामीण विकास की रीढ़ बने हुए हैं, ऐसे में उनके हितों की अनदेखी न्यायसंगत नहीं है।

केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि कार्मिक हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण सुझावों पर यथासंभव सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मनरेगा कर्मियों के मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा और संरचनात्मक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में अवश्य लाया जाएगा, ताकि इस दिशा में ठोस निर्णय लिया जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देव प्रताप सिंह, कोर कमेटी सदस्य उदय राज शर्मा, अतुल राय एवं विनय द्विवेदी भी उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में केंद्र सरकार से अपेक्षा जताई कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कार्मिकों को आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से सशक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अन्नपूर्णा भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थायें 29 दिसम्बर को आयोजित बैठक में आवेदन दें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने जनपद में अन्नपूर्णा भवन निर्माण हेतु इच्छुक कार्यदायी संस्थाओ को सूचित किया है कि 29 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे विकास भवन सभागार में अन्नपूर्णा भवन अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गयी है। बैठक में इच्छुक कार्यदायी संस्थायें अपने कार्यानुभव व अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ जिला अनुश्रवण समिति के समक्ष अन्नपूर्णा भवन निर्माण हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। जिला अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कार्यदायी संस्थाओं के योग्यता आदि के परीक्षणोपरान्त निर्माण कार्य आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु जिला पूर्ति कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। निर्मित किये जाने वाले उचित दर दुकान (अन्नपूर्णा भवन) का मानचित्र खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।

फर्मे जेम पोर्टल पर लेखन सामग्री किट क्रय किये जाने हेतु 05 जनवरी को करें प्रतिभाग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आदित्य प्रजापति ने बताया है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु लेखन सामग्री किट क्रय किये जाने हेतु जेम पोर्टल द्वारा बिड/निविदा के माध्यम से क्रय के आधार पर नियमानुसार न्यूनतम एल-1 दर वाली जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड एवं अनुभवी फर्म का चयन किये जाने हेतु क्रमशः जेम बिड संख्या जेम/2025/बी/7022524 दिनांक 20 दिसम्बर में 05 जनवरी 2026 को अपरान्ह 3.30 बजे तक प्रतिभाग कर सकता है। निर्धारित निविदा की शर्तें जेम पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इच्छुक फर्मे तकनीकी एवं वित्तीय भाव से सम्बन्धित अभिलेख एवं शर्तें जेम पोर्टल से डाउनलोड कर सकते है तथा निर्धारित तिथि तक ही जेम पोर्टल पर सबमिट कर सकते है। टेक्निकल बिड वैध पाये जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा।

संक्षिप्त खबरें

नैन्सी ने विज्ञान क्विज प्रतियोगिता पाया प्रथम स्थान

हमीरपुर – गोहाण्ड ब्लॉक संसाधन केन्द्र में सोमवार के दिन राष्ट्रीय अविष्कार अभियान कार्यक्रम के तहत विज्ञान क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में जिज्ञासा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने, प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने तथा विज्ञान/गणित एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय अविष्कार अभियान'' के तत्वाधान में इस विज्ञान क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।प्रतियोगिता में गोहाण्ड विकासखण्ड के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कई बालक एवं बालिकाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। विज्ञान क्विज़ प्रतियोगिता खण्ड शिक्षा अधिकारी गोहाण्ड शैलेश कुमार के दिशा निर्देश में ए.आर.पी. रामजीवन एवं महेन्द्र कुमार द्वारा विधिवत रूप से आयोजित की गई। प्रतियोगिता में चयनित शिवा उच्च प्राथमिक विद्यालय रावतपुरा स्थान प्रथम, नैन्सी उच्च प्राथमिक विद्यालय रहॅंक द्वितीय स्थान, मुस्कान उच्च प्राथमिक विद्यालय जखेडी तृतीय स्थान प्राप्त किया इनके अतिरिक्त 40 अन्य बाल वैज्ञानिक शील्ड, पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र पाकर चेहरे खिल उठे कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह, राजा बाबू, सौरभ त्रिपाठी,डालचन्द्र एवं समस्त बीआरसी स्टॉफ़ उपस्थित रहा।

नलकूप में लगी आग, भूसा व कृषि उपकरण जले, 70 हजार के नुकसानका अनुमान

हमीरपुर :– सुमेरपुर क्षेत्र के ग्राम सौंखर में बीती रात एक नलकूप में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में नलकूप में रखा भूसा और कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कई उपकरण जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। आग से करीब 70 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रामीण सभाजीत कुशवाहा ने बताया कि रात लगभग 10 बजे नलकूप से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दीं। उस समय उनके माता-पिता नलकूप के पास ही मौजूद थे। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थिति को देखते हुए शोर मचाया गया, जिस पर पास-पड़ोस के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पत्योरा पुलिस चौकी प्रभारी निशांत दुबे ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

भरखरी टीम ने शेरगढ़ क्रिकेट क्लब को 70 रनों में समेटा

हमीरपुर :– मुस्करा विकासखण्ड क्षेत्र के निवादा गांव ने चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार के दिन दो मैच खेले गए।पहला मैच शेरगढ़ क्रिकेट क्लब निवादा और भरखरी के बीच खेला गया और दूसरा मैच बिवांर और एल पी सी क्रिकेट क्लब के बीच हुआ। पहले मैच में शेरगढ़ क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर भरखरी को बल्लेबाजी का मौका दिया।भरखरी टीम ने दस ओवरों में 97 रन बनाए।वहीं शेरगढ़ क्रिकेट क्लब नौवें ओवर में महज 70 रनों में सिमट गई।भरखरी के श्यामजी ने 23 गेंदों में 39 रन बनाए ,जिसे मैन ऑफ मैच दिया गया।शेरगढ़ क्रिकेट क्लब के कश्यप द्वारा खेली गई 17 गेंदों में 38 रनों की पारी भी मैच नहीं जिता सकी।दूसरे मैच में एल सीसी क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिवांर टीम को 74 रनों के लक्ष्य दिया।बिवांर टीम ने नौ ओवर तीन गेंदों में मैच जीत लिया।बिवांर टीम से ज्ञानेंद्र सिंह ने 17 गेंदों में 31 रन बनाए और आखिरी गेंद में चौका मारकर अपनी टीम के लिए विजयी शॉट मारा।

श्रीभूमि जिले के किशोरीपुर गांव में 15 लाख रुपये के कम्युनिटी हॉल के निर्माण में व्यापक अनियमितताएं, इंजीनियर ने जांच का आश्वासन दिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि– वर्तमान सरकार 'सबका साथ सबका विकास' इस नारे के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकासपरक कार्यों के जरिए विकास के लक्ष्य के लिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी समेत उच्च मानक की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। ताकि आम लोगों अन्य परियोजनाओं के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन श्रीभूमि जिले की रामकृष्णनगर विधानसभा के चेरागी ग्राम पंचायत के किशोरीपुर गांव में 15 लाख रुपये के कम्युनिटी हॉल के निर्माण में व्यापक अनियमितताएं हो रही हैं, स्थानीय लोगों का आरोप है। रामकृष्णनगर जिला के किशोरीपुर गांव के उक्त निर्माण के लिए लगभग 15 लाख रुपये सरकार की ओर से आवंटित किए गए थे। कुछ महीने पहले इस परियोजना का शिलान्यास लोकप्रिय विधायक विजय मालाकार ने किया था। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी स्थानीय निर्माण समिति और से क्या जा रहा है। इस बीच, काम शुरू करने वाले ठेकेदार ने विभागीय निर्देश और सरकार के गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए मंजूरशुदा निर्माण कार्य निम्न गुणवत्ता के साथ चलाया जा रहा है। अधिकारी मशीन से तोड़े गए पत्थरों के स्थान पर निम्न गुणवत्ता वाली नदी की मिट्टी मिलाकर पत्थर (रिबर चिप्स) साफ किए बिना थोड़े सीमेंट को मिलाकर कुटीर के निचले हिस्से की ढलान करते हैं। इससे मंडप के अंदरूनी हिस्से बहुत कमजोर हो जाएगा, ऐसा स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। इस विषय पर रामकृष्णनगर पर्ट डिवीजन के उक्त कार्य के जिम्मेदार इंजीनियर बानीब्रत

चक्रवर्ती से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि विषय की जाँच करके आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें निर्माण कार्य अपनी जिम्मेदारी पर करना होता तो उन्हें अवसर नहीं दिया गया। नतीजतन वे मजबूर होकर स्थानीय निर्माण समिति के पास वास्तविक कार्य छोड़ देते हैं। हालांकि जनता इंजीनियर के बयान को केवल आत्म पक्षीय समर्थन के रूप में देख रही है। उनके अनुसार इंजीनियर की मदद के बिना निर्माण समिति ने विभागीय निर्देशों की अवहेलना की और अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो इंजीनियर और विभागीय अधिकारी अनैतिक कार्य को क्यों नहीं रोक रहे हैं। इस स्थिति में जनता की मांग है कि निर्माण कार्य केवल विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए। निर्देशिका का उल्लंघन किया गया है, इसे तोड़कर फिर से किया जाए। अन्यथा भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।

लैंगिक अपराधों व महिला उत्पीड़न से सम्बंधित कार्यक्रम का हुआ आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :– जिला मुख्यालय के डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार में सोमवार के दिन ,कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष महेंद्र पांडेय रहे।जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। बताते चलें कि प्रदेश में बीते 22 सितंबर से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन हेतु मिशन शक्ति के विशेष अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में दिनांक 17.12.2025 से दिनांक 22.12.2025 तक की अवधि में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का प्रशिक्षण आयोजन कराए जाने के शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों में गठित आंतरिक समितियों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। विभागों में संचालित योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध पर उपस्थिति लोगो को (DLS) सचिव डॉ महेंद्र पांडेय जी ने शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एवं सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है, जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ और विकास में बाधा है, तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। भारत सरकार द्वारा 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग के सभी कार्मिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दीप्ति अग्निहोत्री (बाल संरक्षण इकाई) द्वारा किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

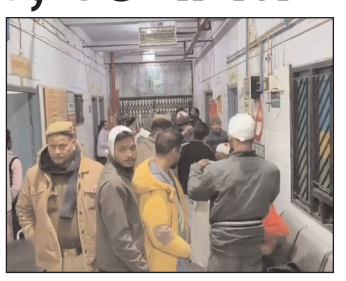

बलिया में 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर होगा जनपद स्तरीय किसान मेला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को बलिया जिले में किसान सम्मान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम ऑफिसर्स क्लब परिसर में सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा। किसान सम्मान दिवस के मौके पर जिले में परंपरागत खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मान प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में कृषि विभाग के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य एवं गन्ना विभाग से जुड़े प्रगतिशील किसान भी भाग लेंगे। सभी संबंधित विभागों से जुड़े किसान इस आयोजन में सहभागिता कर अपने अनुभव साझा करेंगे। यह आयोजन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा) योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी के रूप में किया जा रहा है। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक विभाग से 25-25 प्रगतिशील किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और आधुनिक व परंपरागत कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करना है।

मुबारकपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल का मना स्थापना दिवस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आज़मगढ़। मुबारकपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल (सीबीएसई से संबद्ध 10+2) में विद्यालय का स्थापना दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री विवेक जी,ढ्ढ्र,आयुक्त, आज़मगढ़ मंडल रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री सुनील कुमार सिंह जी, आई.पी.एस., पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी), आज़मगढ़ मंडल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की निदेशक व प्रधानाचार्य रेखा सिंह तथा सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक अयाज अहमद खान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि श्री विवेक जी ने अपने संबोधन में कहा कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, अनुशासन एवं संस्कारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत व ईमानदारी से आगे बढ़ने का संदेश दिया।

विशिष्ट अतिथि श्री सुनील कुमार सिंह जी ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, अनुशासन और कानून के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही कल का सशक्त राष्ट्र निर्माण करेंगे। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। नृत्य, गीत, नाटक एवं प्रेरणादायक प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षकगण एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों व आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

राजस्व न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया का होरा रहा उल्लंघन- अरविंद पाठक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आजमगढ़। जिलाधिकारी आजमगढ़ की न्यायिक कार्यशैली से नाराज होकर दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविन्द कुमार पाठक की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने चक्रमण कर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई है। जिसमे दो बिन्दु पर प्रस्ताव पास कर न्यायिक कार्य से विरत रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार पाठक ने कहा कि जिलाधिकारी समेत सभी राजस्व न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। स्थिति यह है कि कालबाधित दावे, तजवीजसानी, अपील, निगरानी स्वीकार नहीं किये जा रहे और न ही उन्हें आन लाइन वाद दर्ज किया जा रहा है। जिससे नैसर्गिक न्याय का हनन हो रहा है। उक्त के संबंध में जिलाधिकारी से कई बार वार्तालाप हुआ लेकिन आज तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गई। जिससे क्षुब्ध होकर अधिवक्ताओं को प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ा। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो जनपद के सभी बार संगठन एक राय होकर एक उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी आजमगढ़ की होगी।

मंत्री रणधीर सिंह ने कहाकि राजस्व न्यायालयों द्वारा बगैर सुनवाई के ही वादों को खारिज किया जाना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। जिससे वादकारियों का काफी अहित है और न्याय मिल पाना असंभव हो गया है। राजस्व न्यायालयों के मनमाने रवैये को बार बदाश्त नहीं करेगा। शीघ्र ही डीएम ने आवश्यक कदम नहीं उठाये तो हम मुखर होने को बाध्य होंगे। अधिविक्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभी अधिवक्ता उपस्थित रहे।

किसान सम्मान दिवस पर जनपद व विकास खंड स्तर पर होंगे कार्यक्रम

हमीरपुर :– भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आगामी सोमवार के दिन जनपद में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सुबह दस बजे राजकीय महिला महाविद्यालय हमीरपुर में जनपद स्तरीय किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी, गोष्ठी तथा फल एवं शाक-भाजी शो भी आयोजित होंगे, जिसमें जनपद के किसान भाग लेकर अपनी उपज का प्रदर्शन कर सकेंगे।

उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों में भी विकास खंड स्तरीय किसान सम्मान दिवस आयोजित किया जाएगा। विकास खंड कुरारा का कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र कुरारा में संपन्न होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सम्मानित करने के साथ-साथ उन्हें कृषि की नवीन तकनीकों, योजनाओं और उन्नत बीजों की जानकारी देना है। उप कृषि निदेशक ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम में सहभागिता करें और योजनाओं का लाभ उठाएं।

इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर दो पक्षों में मारपीट, छह घायल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :– सदर कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ईदगाह के पास हुई इस घटना में दोनों पक्षों से पिता-पुत्रों सहित कुल छह लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ला निवासी जितेंद्र यादव के पुत्र प्रिंस यादव (18) और दिव्यांश यादव (17) का गौरा देवी मोहल्ला निवासी बाबूलाल भुर्जी के पुत्र संदीप (28) और विजय (18) से इंस्टाग्राम पर मैसेज को लेकर विवाद हो गया था। पहले सोशल मीडिया पर शुरू हुई नोकझोंक धीरे-धीरे बढ़ती चली गई और देर रात यह विवाद आमने-सामने की मारपीट में बदल गया। बताया जाता है कि विवाद बढ़ने पर प्रिंस और दिव्यांश कार से गौरा देवी पहुंचे, जहां दूसरा पक्ष पहले से मौजूद था। इसके बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई। झड़प में एक पक्ष से प्रिंस यादव, दिव्यांश यादव और उनके पिता जितेंद्र यादव घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से संदीप, विजय और उनके पिता बाबूलाल भुर्जी को चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। सोशल मीडिया सेल के अनुसार सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तहरीर मिलने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

श्रीभूमि जिले के चेरागी ग्राम पंचायत के विकलांग राहुल नामशूद्र के अभिभावक ने सरकार से इलाज के लिए आर्थिक मदद की अपील

● **मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का ध्यान।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूम– जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के चेरागी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 में दिहाड़ी मजदूर संजीत नामशूद्र का बेटा राहुल नामशूद्र (9) जन्म से ही विकलांग है और बोल नहीं पा रहा है। परिवार का एकमात्र कमाने वाला एक दिहाड़ी मजदूर है और अपने बेटे का इलाज कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि, राज्य की भाजपा सरकार ने विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अन्य लाभ प्रदान किए हैं। अब सवाल पिछले साल के ग्राम पंचायत अध्यक्ष या वार्ड सदस्य की भूमिका पर संदेह है। क्या उन्होंने भाई-भतीजावाद की नीति अपनाई?

दिव्यांगों की मां फुलमती रॉय ने कहा, 'मौजूदा विधायक बिजय मालाकार निर्वाचन क्षेत्र के कोने-कोने में विभिन्न तरीकों से असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि, स्थानीय नेताओं के कारण उन्हें आज तक सरकारी लाभ से वंचित किया जा रहा है। हालांकि, उन्हें आधिकारिक तौर पर व्हीलचेयर और अरुणद्वय के लिए आवेदन किया है, बाकी भगवान पर छोड़ दिया है। हालांकि बेटे के इलाज के लिए राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और विधायक विजय मालाकार सहित जिले की नमःशूद्र समिति की कृपा दृष्टि की कामना करते हैं। ताकि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इलाज किया जा सके

बलिया नगर के वार्ड नंबर 5 में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम हेतु छिड़काव की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। नगर क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को लेकर वार्ड नंबर 5 के लोगों ने नगर प्रशासन से नियमित कीटनाशक छिड़काव कराने की मांग की है। स्वतंत्र प्रभात से वार्ता के दौरान स्थानीय नागरिकों ने बताया कि वार्ड में जगह-जगह जलजमाव और नालियों की समुचित सफाई न होने के कारण मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। मांग करने वालों में जितेंद्र चतुर्वेदी,अजीत पांडे, बृजेश पांडे, दीपक तिवारी, रजनीश उपाध्याय, राकेश विक्रम सिंह,अखिलेश तिवारी, आशीष मिश्रा, ईलू पांडे सहित अन्य लोग शामिल रहे। लोगों का कहना है कि कई दिनों से वार्ड में फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव नहीं कराया गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की कि वार्ड नंबर 5 में तत्काल प्रभाव से नियमित छिड़काव कराया जाए, नालियों की सफाई कराई जाए तथा जलजमाव वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वार्ड में बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ सकता है। नागरिकों को उम्मीद है कि नगर प्रशासन इस गंभीर समस्या पर ध्यान देते हुए जल्द आवश्यक कदम उठाएगा।

सिलापथार में लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव का सफलतापूर्वक संपन्न

असम धेमाजी । फिट यूथ ' विकसित भारत, 2025 उद्देश्य को आगे रखते हुए लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के चिचिबरगांव विधानसभा क्षेत्र के सिलापथार महाविद्यालय खेल मैदान में एक दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के नौ विधानसभा क्षेत्रों के युवाओं की खेल के प्रतिभाओं के विकास के लिए एक मंच दिलाने की प्रयास में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में युवाओं के लिए दौड़, वॉलीबॉल, कबड्डी सहित कुल छह प्रकार की खेल आयोजित की गई है। सुबह लखीमपु लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रदान बरुआ, कैबिनेट मंत्री रनोज पेगू ,विधायक भुवन पेगू, बलिन चेतिया, मानव डेका सहित धेमाजी जिला भाजपा दल के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में खेल महोत्सव का झंडा फहराया गया एवं खेल का अनुष्ठानिक तौर पर शुभारंभ किया गया। खेल का अंत में जिला उपायुक्त के उपस्थिति में सभी प्रकार के खेलो का विजयी प्रतियोगियों को मानपत्र,मेडल, से सम्मानित किया गया।

मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में आज़मगढ़ कांग्रेस का जोरदार विरोध मार्च

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आजमगढ़– सोमवार को ज़िला कांग्रेस कमेटी, आज़मगढ़ ने ज़िलाध्यक्ष श्री कौशल कुमार सिंह 'मुन्ना राय ' के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक विरोध मार्च का आयोजन किया। यह मार्च ज़िला कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट मार्ग एवं रैदोपुर तिराहा होते हुए गांधी प्रतिमा तक निकाला गया। इस अवसर पर आज़मगढ़ कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा मनरेगा (स्न्नहत्रक्ष्वन्न) का नाम बदलने तथा इसके मूल ढांचे को कमजोर करने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा की। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा माने जाने वाले 'काम के अधिकार' को समाप्त करने की एक सुनियोजित साजिश है।

मुख्य बिंदुः– मांग बनाम बजट का खेलः मनरेगा एक मांग आधारित कानून था, जिसमें काम मांगना मजदूर का कानूनी अधिकार था। मोदी सरकार की मनमानी से इसे बजट आधारित बना दिया गया है, जिससे मजदूरों को उनकी जरूरत के अनुसार काम मिलना कठिन हो गया है।

राज्यों पर आर्थिक बोझः केंद्र सरकार ने अपने वित्तीय हिस्से में कटौती कर राज्यों पर 40% तक का बोझ डाल दिया है। पहले केंद्र 90% खर्च वहन करता था। यह संघीय ढांचे पर सीधा हमला है।

महात्मा गांधी के नाम का अपमानः यूपीए सरकार ने राष्ट्रपिता के सम्मान में इस योजना का नाम रखा था। आज केवल श्रेय लेने की होड़ में बापू के नाम को राष्ट्रीय चेतना से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।

तकनीक का कुचक्रः एनएमएमएस (NMMS), आधार आधारित भुगतान और अब एआई (AI) ऑडिट जैसे प्रावधानों ने लाखों मजदूरों को पहले ही काम और मजदूरी से वंचित किया है।

इस दौरान ज़िलाध्यक्ष श्री कौशल कुमार सिंह 'मुन्ना राय' ने कहा,

मनरेगा गरीबों के लिए कोई दया नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। भाजपा सरकार इस अधिकार को छीनने और महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। सरकार को यह गरीब-विरोधी विधेयक तुरंत वापस लेना होगा और मनरेगा के मूल 'गारंटी' वाले स्वरूप को बहाल करना होगा। इस विरोध मार्च में राजाराम यादव, राहुल राय, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, अंसार अहमद, तेज बहादुर यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, अजीत राय, बेलाल बेग, रमेश राजभर, शिव मंगल सिंह, संतोष सिंह, हाजी इफ्तिखार, मो. आमिर, मुरारी राय, नवनीत राय, प्रदीप यादव, हरिओम उपाध्याय , दिनेश सरोज , अजय कुमार , मैनेजर यादव रामानंद सागर , राम कुमार यादव , राकेश गुप्ता , हरेंद्र सिंह , श्यामदेव यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।